

SCs व STs के वरिद्ध अत्याचार पर रपिर्स्ट

प्रलिमिंस के लयि:

[सरवोच्च न्यायालय](#), [अनुसूचति जात](#), [अनुसूचति जनजात](#), [अग्रमि जमानत](#), [वशिष अदालतें](#)

मेन्स के लयि:

अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अत्याचार नवारण) अधनियिम, 1989, नीतयिों के डिजाइन और कार्यानवयन से उत्पन्न मुद्दे

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अत्याचार नवारण) अधनियिम, 1989 के तहत एक रपिर्स्ट जारी की है, जसिमें वर्ष 2022 में अनुसूचति जातयिों के खलिफ अत्याचार की स्थति पर प्रकाश डाला गया है।

अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के वरिद्ध अत्याचार पर रपिर्स्ट के मुख्य नषिकर्ष क्या हैं?

- **केस संबधी आँकडे:** वर्ष 2022 में [अनुसूचति जातयिों \(SCs\)](#) के खलिफ अत्याचार के 51,656 मामले और [अनुसूचति जनजातयिों \(STs\)](#) के खलिफ 9,735 मामले दर्ज कयि गए। उल्लेखनीय है कि अनुसूचति जातयिों (SCs) के 97.7% मामले और अनुसूचति जनजातयिों (STs) के 98.91% मामले सरिफ 13 राज्यों में केंद्रति थे।
- **सर्वाधिक घटनाओं वाले राज्य:**
 - अनुसूचति जातयिों के लयि: नमिनलखिति 6 राज्यों में कुल मामलों का लगभग 81% हसिंसा दर्ज कयिा गया।
 - उत्तर प्रदेश: 12,287 मामले (23.78%)
 - राजस्थान: 8,651 मामले (16.75%)
 - मध्य प्रदेश: 7,732 मामले (14.97%)
 - अन्य राज्य: बहिर 6,799 (13.16%), ओडशिा 3,576 (6.93%), और महाराष्ट्र 2,706 (5.24%)।
 - अनुसूचति जनजातयिों के लयि:
 - मध्य प्रदेश: 2,979 मामले (30.61%)
 - राजस्थान: 2,498 मामले (25.66%)
 - ओडशिा: 773 मामले (7.94%)
 - अन्य राज्य: 691 मामले के साथ महाराष्ट्र (7.10%) और 499 मामले के साथ आंध्र प्रदेश (5.13%)।
- **चारज शीट और जाँच :**
 - अनुसूचति जात से संबधति मामले: अनुसूचति जात से संबधति 60.38% मामलों में चारज शीट दायर की गई, जबकि झूठे दावों या सबूतों की कमी जैसे कारणों से 14.78% मामलों में ही अंतिम रपिर्स्ट दी जा सकी।
 - अनुसूचति जनजात से संबधति मामले: अनुसूचति जनजात से संबधति 63.32% मामलों में चारज शीट दायर की गई, जबकि 14.71% मामलों में अंतिम रपिर्स्ट प्रस्तुत की गई।
 - वर्ष 2022 के अंत तक, अनुसूचति जातयिों से जुड़े 17,166 मामले और अनुसूचति जनजातयिों से जुड़े 2,702 मामले अभी भी जाँच के अधीन थे।
- **दोषसदिधिर (Conviction Rates):**
 - अधनियिम के तहत दोषसदिधिर 2020 में 39.2% से घटकर 2022 में 32.4% हो गई है, जो न्यायकि परणामों में चतिाजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- **बुनयादी ढाँचे की कमयाँ:**
 - 14 राज्यों के 498 जिलों में से केवल 194 जिलों ने अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के वरिद्ध अत्याचारों के मुकदमों के

त्वरति नपिटान के लयि वशिष अदालतें स्थापति की हैं।

- अत्याचारों से ग्रस्त वशिषिट ज़िलों की पर्याप्त रूप से पहचान नहीं की गई है, उत्तर प्रदेश में अत्याचारों से ग्रस्त कसिी भी क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है, जबकि वहाँ सबसे अधिक मामले हैं।

■ संरक्षण प्रकोषट:

- आंध्र प्रदेश, असम, बहिर, गुजरात, तमलिनाडु आदि सहति वभिनिन राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों के साथ-साथ दलिी, जम्मू और कश्मीर तथा पुडुचेरी जैसे केंद्र शासति प्रदेशों में एससी/एसटी संरक्षण प्रकोषट स्थापति कयि गए हैं।

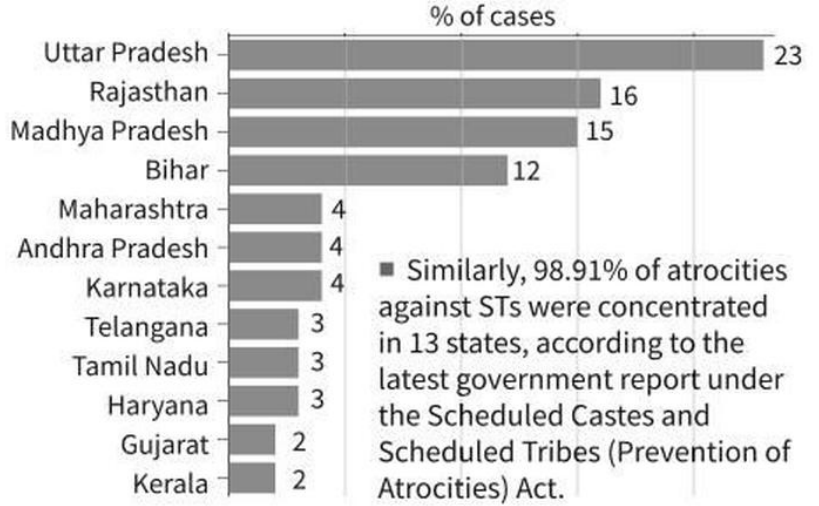
//

Atrocities on Dalits, tribal people

The chart shows the States accounting for 97.7% of total cases of atrocities against members of Scheduled Castes during the year 2022.



Source: Ministry of Social Justice and Empowerment



अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों के खलिफ अपराध के क्या कारण हैं?

- जातगित पूरवाग्रह और असपृश्यता: गहरी जड़ें जमाए हुए जातगित पदानुक्रम भेदभावपूरण प्रथाओं को कायम रखते हैं, जहाँ एससी/एसटी समुदायों को प्रायः "नमिन" माना जाता है और उनकी जनम-आधारति जातगित पहचान के कारण सामाजकि बहषिकार और हसिा का शकिार होना पडता है।
- भूमि विविद और अलगाव: ऐतहिसकि रूप से भूमि स्वामतिव से वंचति, अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति समुदायों को भूमि तिक पहुँच को लेकर नरितर संघर्ष का सामना करना पडता है, जिसके कारण प्रमुख जातयिों के साथ विविद होता है।
- आर्थकि रूप से वंचति होना: शकिषा, रोज़गार और आर्थकि संसाधनों तक सीमति पहुँच के कारण अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति समूहों की सुभेदयता बढ जाती है, जिससे वे प्रभुत्वशाली समुदायों द्वारा शोषण और हसिा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- सामाजकि और राजनीतकि शक्ति का असंतुलन: प्रभावशाली उच्च जातयिों प्रायः असंगत राजनीतकि और सामाजकि प्रभाव रखती हैं, जिससे वे कानूनी परिणामों के भय के बिना भेदभावपूरण प्रथाओं को बनाए रखने में सक्षम हो जाती हैं।
- कानून का अपर्याप्त करयानवयन: यदयपि इन समुदायों की सुरक्षा के लयि एससी/एसटी (अत्याचार नविरण) अधनियम जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन कमजोर प्रवर्तन, पुलिस और नौकरशाही पूरवाग्रह के साथ मलिकर प्रायः जाति-आधारति हसिा के पीड़ितों के लयि न्याय में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- राजनीतकि अवसरवादति: कभी-कभी राजनीतकि नेतृत्वकर्त्ता चुनावी लाभ के लयि जातगित तनाव को बढा देते हैं, जिससे समुदायों के बीच धरुवीकरण और संघर्ष में वृद्धि होती है।

अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति (अत्याचार नविरण) अधनियम, 1989 क्या है?

- परिचय: अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति (अत्याचार नविरण) अधनियम, 1989, जिससे SC/ST अधनियम 1989 के रूप में भी जाना जाता है, एससी और एसटी के सदस्यों को जाति-आधारति भेदभाव और हसिा से बचाने के लयि अधनियमति कयि गया था।
- उद्देश्य:
 - इस अधनियम का उद्देश्य संवधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 की रक्षा करना, वंचति समुदायों की सुरक्षा करना तथा नागरकि अधिकार संरक्षण अधनियम, 1955 जैसे पछिले कानूनों की कमयिों को दूर करना है।
- ऐतहिसकि संदर्भ: यह अधनियम असपृश्यता (अपराध) अधनियम, 1955 और नागरकि अधिकार संरक्षण अधनियम, 1955 पर आधारति है, जो जाति के आधार पर असपृश्यता तथा भेदभाव को समाप्त करने के लयि स्थापति कयि गए थे।
- नियम और कारयानवयन:
 - यह केंद्र सरकार को अधनियम के कारयानवयन के लयि नियम बनाने हेतु अधिकृत करता है, जबकि राज्य सरकारें और केंद्रशासति प्रदेश

- गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग: पीड़ितों को समर्थन प्रदान करने और उनके अधिकारों की वकालत करने के लिये गैर-सरकारी संगठनों तथा नागरिक समाज समूहों के साथ साझेदारी कर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में उनकी मांगों पर विचार किया जाए।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. भारत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के वरिद्ध नरितर हो रहे अत्याचारों के लिये उत्तरदायी प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 कतिना प्रभावी है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????

प्रश्न. सवतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रतभिदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य वधिकि पहलें क्या हैं ? (2017)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/report-on-atrocities-against-scs-and-sts>

